गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 014
दि. 14.05.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तमिलनाडु विधानसभा में विजय की बड़ी परीक्षा पास फ्लोर टेस्ट में TVK सरकार को मिला मजबूत समर्थन

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में बुधवार का दिन बेहद अहम साबित हुआ, जब अभिनेता से राजनेता बने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। लंबे राजनीतिक घटनाक्रम, जोड़तोड़ की चर्चाओं और विपक्षी रणनीतियों के बीच हुए इस शक्ति परीक्षण में विजय सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में हुए विश्वास मत के दौरान सरकार के खिलाफ 22 वोट पड़े, जबकि पांच विधायक मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इस जीत के साथ मुख्यमंत्री विजय ने न केवल अपनी सरकार को स्थिरता का संदेश दिया, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में अपनी पकड़ भी मजबूत कर ली।

फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा का माहौल बेहद गर्म और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विभिन्न दलों के रुख को लेकर अटकलें तेज थीं। कई राजनीतिक दलों ने आखिरी समय तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। लेकिन जैसे-जैसे कार्यवाही आगे बढ़ी, टीवीके सरकार के समर्थन में विपक्षी और क्षेत्रीय दलों का झुकाव स्पष्ट होता गया। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और IUML जैसे दल खुलकर विजय सरकार के समर्थन में सामने आए। इन दलों का समर्थन विजय सरकार के लिए निर्णायक साबित हुआ।

कांग्रेस ने विधानसभा में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वह तमिलनाडु में राजनीतिक स्थिरता और भाजपा विरोधी राजनीति को ध्यान में रखते हुए विजय सरकार का समर्थन करेगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि राज्य में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट रखना समय की जरूरत है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) ने भी सरकार के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। पार्टी का कहना था कि टीवीके सरकार की शुरुआती नीतियां सामाजिक न्याय और जनकल्याण की दिशा में सकारात्मक संकेत दे रही हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने भी विजय सरकार को समर्थन देते हुए कहा कि तमिलनाडु में लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राजनीति को मजबूत करने के लिए यह जरूरी कदम है।

विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) ने भी सरकार को समर्थन दिया, लेकिन इसके

साथ एक महत्वपूर्ण मांग भी रखी। पार्टी ने तमिलनाडु में महाराष्ट्र और कर्नाटक की तर्ज पर अंधविश्वास विरोधी कानून लागू करने की अपील की। वीसीके विधायक वन्नी अरसु ने सदन में कहा कि धर्मनिरपेक्ष दलों ने बिना शर्त समर्थन दिया है और उन्हें विश्वास है कि विजय सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने भी टीवीके सरकार का समर्थन करते हुए विजय सरकार की शुरुआती कार्यशैली की सराहना की। पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसले जनता को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। खासतौर पर राज्य में 717 शराब दुकानों को बंद करने के निर्णय को IUML ने साहसिक और जनहितकारी कदम बताया। पार्टी का कहना था कि इससे सामाजिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं व गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। विधानसभा में शराब दुकानों को बंद करने का मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहा। कई दलों ने इस फैसले की सराहना की। डीएमडीके ने भी विजय सरकार की इस पहल को अच्छा कदम बताते हुए कहा कि इससे समाज में शराब की लत कम करने की दिशा में मदद मिलेगी। हालांकि पार्टी ने कुछ प्रशासनिक मुद्दों पर सवाल भी उठाए। विशेष ड्यूटी पर अधिकारी की नियुक्ति को लेकर डीएमडीके नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई और सरकार से पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की।

इस पूरे घटनाक्रम में डीएमके का रुख सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। डीएमके ने मतदान से पहले सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि पार्टी ने सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ मतदान नहीं किया, लेकिन कार्यवाही के दौरान सरकार की कुछ नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल जरूर उठाए। डीएमके विधायक थामिमुन अंसारी ने विशेष ड्यूटी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। वहीं डीएमके नेता एमएच जवाहरुल्लाह ने तमिल भाषा और तमिल सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार के कार्यक्रमों में तमिल राष्ट्रगान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भाजपा और पीएमके ने इस फ्लोर टेस्ट में अलग रणनीति अपनाई। भाजपा ने विश्वास मत की प्रक्रिया पर खुद को "तटस्थ" बताते हुए मतदान में सक्रिय भागीदारी से दूरी बनाई। भाजपा नेताओं का कहना था कि वे राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और समय आने पर उचित राजनीतिक निर्णय लेंगे। पीएमके की विधायक सौम्या अंबुमणि ने भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी विश्वास मत में मतदान से दूर रहेगी। इसके चलते भाजपा और पीएमके ने कार्यवाही के दौरान वॉकआउट कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दलों ने सीधे विरोध या समर्थन से बचते हुए अपनी राजनीतिक संभावनाओं को खुला रखने की कोशिश की।

वहीं एआईएडीएमके के भीतर फ्लोर टेस्ट को लेकर गहरा विभाजन खुलकर सामने आया। पार्टी प्रमुख एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने विजय सरकार के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया। पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके सरकार का विरोध करेगी और पार्टी लाइन से हटकर जाने वाले विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पार्टी के भीतर एक दूसरा गुट खुलकर विजय सरकार के समर्थन में सामने आ गया। एसपी वेलुमणि और सीवी शनमुगम जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में करीब 30 विधायकों के समूह ने सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी। यह घटनाक्रम एआईएडीएमके के भीतर जारी अंतर्कलह को उजागर करने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में एआईएडीएमके में बड़ा राजनीतिक पुनर्गठन देखने को मिल सकता है।

फ्लोर टेस्ट में जीत के बाद मुख्यमंत्री विजय ने इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तमिलनाडु के विकास, सामाजिक न्याय और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देगी। विजय ने समर्थन देने वाले सभी दलों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार बदले की राजनीति नहीं बल्कि विकास और जनकल्याण की राजनीति में विश्वास करती है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु की जनता ने बदलाव और नई राजनीति के लिए समर्थन दिया है और उनकी सरकार उस भरोसे को टूटने नहीं देगी।

तमिलनाडु की राजनीति में विजय की यह जीत केवल एक फ्लोर टेस्ट तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे राज्य की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत भी माना जा रहा है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय ने बहुत कम समय में खुद को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित किया है। फ्लोर टेस्ट में मिली सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अब केवल जनभावनाओं का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्ता संचालन की वास्तविक ताकत बन चुकी है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बहुमत परीक्षण के बाद विजय सरकार को फिलहाल स्थिरता मिल गई है, लेकिन आने वाले दिनों में विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगी दलों की अपेक्षाओं को संतुलित रखते हुए प्रशासनिक प्रदर्शन साबित करने की होगी।

जनता को मितव्ययी रहने की सलाह, नेताओं द्वारा किए जा रहे फिजूलखर्ची पर सवाल

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

हमारे यहाँ एक कहावत है कि "समझदार व्यक्ति को अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए और मूर्ख को यह सिखाया जाना चाहिए कि यदि वह अच्छा ससुर है, तो उसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए।" यह कहावत आज के नेताओं पर कुछ हद तक लागू होती प्रतीत होती है, जिनके शब्द और कार्य अलग हैं।

एक तरफ तो नेता मीडिया की मदद से झूठी लोकप्रियता हासिल करने के झूठे प्रयास में जनता को सूफी उपदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वही नेता बेहिसाब पैसा खर्च करके यह साबित कर रहे हैं कि हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। इस उथल-पुथल भरे कलियुग में, जब जनता दो रुपये का भोजन भी मुश्किल से पा रही है, तब उन्हें बुरी तरह पीटने जैसे "बलिदान" की बात करना कितना उचित है? इसके बावजूद,

देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रुपये का लगातार गिरता मूल्य है। लेकिन इसी दौरान पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी, जो लगातार चुनावी मोड में थे, इन ढाई महीनों में कटौती या मितव्ययिता का नाम तक नहीं ले सके, न ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाईं ताकि मतदाता नाराज न हों। भाजपा को भी चुनावों में इसका फायदा मिला। लेकिन इन फायदों के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था लगातार और भी कमजोर होती चली गई। नतीजतन, स्थिति अंततः इतनी बिगड़ गई कि पानी गर्दन तक बहने लगा, और हमारे प्रधानमंत्री ने जनता के लिए "संकल्प" घोषित करना शुरू कर दिया, जैसे मितव्ययी बनें, पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, सोना न खरीदें, तेल का उपयोग कम करें आदि। लेकिन सवाल यह है कि इन "संकल्पों" को लागू करने में इतना समय क्यों लगा? चुनावी लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से नुकसान पहुंचाना किस तरह की नीति है?

प्रधानमंत्री ने ढाई महीने बाद भी जनता से जिन मितव्ययिता उपायों की बात की है, उन्हें शुरू में लागू क्यों नहीं किया? इतना ही नहीं, क्या इन मितव्ययिता उपायों या प्रस्तावों को लागू करने का दायित्व केवल जनता का है? उन नेताओं या बाबुओं का नहीं जो सरकार के लाभ उठाते हैं?

वैश्विक संकट के समय में, जनता को मितव्ययी होना चाहिए और अपने नागरिक कर्तव्यों का शत प्रतिशत निर्वाह करना चाहिए, लेकिन नेताओं और अधिकारियों को पहले इसे लागू करना होगा। जो कि फिलहाल होता हुआ प्रतीत नहीं होता।

अंजनाद्री मंदिर में 25 लाख रुपये के 'सोने' के आभूषण तांबे के निकले, दान को लेकर विवाद

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

भगवान हनुमान की जन्मभूमि माने जाने वाले प्रसिद्ध अंजनाद्री पहाड़ी मंदिर में दिए गए दान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि आधिकारिक सत्यापन के दौरान 2.5 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण सोने की परत चढ़े तांबे के आभूषण पाए गए हैं।

यह घटना तब सामने आई जब हैदराबाद के उद्योगपति महेश रेड्डी ने 8 मई को मंदिर में एक सजावटी मुकुट, एक चक्र और एक गदा दान की। उद्योगपति ने गंगावती विधायक गली जनार्दन रेड्डी के साथ मंदिर का दौरा किया था, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनके एक करीबी सहयोगी ने देवता को लगभग 2.5 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण दान किए हैं।

हालांकि, सरकारी खजाने में आभूषणों को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने से पहले, जिला अधिकारियों को अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सहायक आयुक्त

महेश मालागीती के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों में से केवल 28 ग्राम ही असली सोना था। शेष भाग कथित तौर पर तांबे के बने थे जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि व्यापारी आभूषणों की आधिकारिक खरीद रसीद या प्रामाणिकता संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने में विफल रहा। सूत्रों के अनुसार, दानकर्ता के अनुरोध पर इन आभूषणों का उपयोग देवता को केवल दो दिनों के लिए सुशोभित करने के लिए किया गया था।

इस खुलासे के बाद, जिला प्रशासन ने महेश रेड्डी को नोटिस जारी कर आभूषणों के वैध बिल और वास्तविक मूल्य का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकारियों ने उचित दस्तावेज जमा होने तक दान की गई वस्तुओं को सरकारी खजाने में जमा करने से भी इनकार कर दिया है। इस घटना ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच व्यापक बहस छेड़ दी है। इससे धार्मिक दान के नाम पर प्रसिद्धि हासिल करने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर की पवित्रता की रक्षा करना और

दान में पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

सूरत की कपड़ा फैक्टरी से मुक्त कराए गए 91 नन्हें बाल मजदूर, सबसे छोटा महज 7 साल का

सरकार, प्रशासन व नागरिक समाज संगठनों की छापे की एक साझा कार्रवाई में ट्रैफिकिंग के जरिए लाए गए और सूरत की एक कपड़ा फैक्टरी में मामूली पैसों पर खटाए जा रहे 91 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए इन बच्चों की उम्र सात से 14 के बीच है। हालांकि भनक लगते ही सभी ट्रैफिकर और फैक्टरी मालिक मौके से फरार हो गए। मुक्त कराए गए बच्चों में से ज्यादातर राजस्थान के जनजातीय इलाकों के हैं जबकि तीन उत्तर प्रदेश के और एक-एक बच्चे झारखंड व बिहार के हैं। इन सभी को बाल कल्याण समिति, सूरत के समक्ष पेश किया गया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गायत्री सेवा संस्थान (जीएसएस) की छानबीन के आधार पर हुई छापे की इस कार्रवाई में जीएसएस सहित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, राजस्थान के 22 पुलिस अफसरों, सूरत के पूना थाने के अफसरों के साथ नागरिक समाज संगठन एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन (एवीए) भी शामिल था। एवीए और जीएसएस देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के काम कर रहे 250 से भी अधिक नागरिक समाज

संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी हैं।

गायत्री सेवा संस्थान महीने भर से सूरत की इस कपड़ा फैक्टरी की निगरानी कर रहा था और छानबीन में यहां बड़ी संख्या में बाल मजदूरों की मौजूदगी की पुष्टि के बाद उसने एनसीपीसीआर को इसकी जानकारी दी। मुक्त कराए बच्चों ने फिर पुलिस को सुराग दिए और उन्हें उन जगहों का पता बताया जहां बाल मजदूरी कराई जा रही थी। गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक डॉ. शैलेंद्र पंड्या ने बताया, "बच्चे हमें एक इमारत के पास ले गए जो बाहर से बंद थी। लेकिन उन्होंने बताया कि अंदर बच्चे काम कर रहे हैं। हम जब अंदर गए तो पाया कि वहां सात साल तक के बच्चों से काम कराया जा रहा था। सभी बच्चे घबराए हुए और बदहवासी की हालत में थे और 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने के बाद थके हुए थे।"

डॉ. पंड्या ने बताया कि अंदर जाने के बाद वे बच्चों की बदहाली देखकर दंग रह गए। आठ साल के एक बच्चे के पास पहनने को शर्ट तक नहीं थी। वह दूसरे बच्चों के पीछे छिप गया और उनसे पूछ रहा था कि क्या कोई थोड़ी देर के लिए अपनी शर्ट उसे दे सकता है। उन्होंने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस और सभी हितधारकों की त्वरित कार्रवाई और मामले को गंभीरता से लेने के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को मुक्त करा पाना संभव हो पाया।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इन बाल दुर्व्यापारियों और फैक्टरी मालिकों ने संदेह से बचने के लिए तमाम तरीके अपना रखे थे। छोटे बच्चों को बिल्कुल सुबह यहां लाया जाता था और फिर इमारत के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए जाते थे। शाम को सात बजे काम की शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद ही दरवाजे खोले जाते थे। इन सभी बच्चों को आस-पास की कालोनियों में बहुत ही दयनीय और अमानवीय हालत में रखा जाता था। एक छोटे से कमरे में 10 से 12 बच्चे रहते थे जहां बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। पूछताछ के दौरान कुछ बच्चों ने बताया कि उनके माता-पिता को पता था कि उन्हें मजदूरी के लिए यहां लाया गया है। उधर, ज्यादातर छोटे बच्चों ने बताया कि उन्हें घुमाने के नाम पर यहां लाया गया था और उन्हें कतई अंदाजा नहीं था कि यहां उनसे मजदूरी कराई जाएगी। यह भी पता चला कि कुछ बच्चे इन कपड़ा इकाइयों में तीन-चार साल से काम कर रहे थे जबकि बाकियों को हाल ही में यहां लाया गया था। मुक्त कराए गए बच्चों में आठ और दस साल के दो भाई भी थे जिन्हें राजस्थान के उदयपुर जिले से लाया गया था।

ट्रैफिकिंग गिरोहों और बाल मजदूरी के तार मजबूती से जुड़े होने को रेखांकित करते हुए जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के राष्ट्रीय संयोजक रवि कांत ने कहा, "इस छापे से यह तथ्य स्थापित हो जाता है कि ट्रैफिकिंग गिरोह कितने संगठित हैं और उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। खास तौर से जनजातीय इलाकों और संवेदनशील परिवारों के बच्चों को झूठे वादों के जाल में फंसा कर ऐसी शोषणकारी परिस्थितियों में धकेल दिया जाता है जहां वे बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और अपना बचपन खो बैठते हैं। यह मामला एक बार फिर अंतरराज्यीय समन्वय को मजबूत बनाने, बाल मजदूरी की मांग व आपूर्ति पर नजर बनाए रखने, बच्चों का शोषण करने वाले नियोक्ताओं और शोषण में शामिल सभी बिचौलियों की धरपकड़ और उनकी जवाबदेही तय करने की तत्काल जरूरत को साबित करता है।"

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
जितेंद्र परमार

संपादकीय

लीक नहीं ठीक

हमारे तंत्र की नाकामी और परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचारियों की बढ़ती सेंध का ही नतीजा है कि पेपर लीक के बाद नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई। भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए तीन मई को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब पौने तेईस लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। ये परीक्षाएं देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5400 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। दरअसल, पेपर लीक होने के आरोपों के बाद जांच एजेंसियों की सिफारिश पर परीक्षा रद्द की गई है। केंद्र सरकार ने कथित रूप से डेटा लीक और धांधली की व्यापक जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि व्यवस्था में विश्वास बहाली के लिए फिर से परीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि एनटीए ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा निष्कर्षों की प्रारंभिक जांच के आधार पर परीक्षा स्थगन का फैसला लिया। निस्संदेह, इस फैसले ने उन लाखों छात्रों को निराश ही किया है जो महीनों से परीक्षा की तैयारी में लगे थे। अब उन्हें नये सिरे से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। नीट प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने एनटीए व केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। कहा जा रहा है कि एनटीए में सुधार नहीं, अब पूरी संरचना बदलने की जरूरत है। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा जा रहा है कि एनटीए के बुनियादी पुनर्गठन की जरूरत है। राजनेता पीपर लीक व प्रश्नपत्रों में गलती सामने आने को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं। साथ ही पूरी परीक्षा प्रणाली को बदलने की मांग की जा रही है। साथ ही एनटीए के उद्देश्य और कार्यक्षमता को लेकर शंका जतायी जा रही है।

वहीं कांग्रेस का आरोप है कि एनटीए द्वारा आयोजित 14 राष्ट्रीय परीक्षाओं में से पांच में पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले उजागर हुए हैं। इनमें जेईई मेन्स 2025 उत्तर कुंजी के दोषपूर्ण होने पर प्रश्नपत्र में 12 प्रश्न वापस लेने पड़े थे। मांग है कि एनटीए को केंद्रीयकृत करने के बजाय संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। वहीं एनटीए कह रहा है कि छात्रों को नया आवेदन नहीं करना होगा, न ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लगेगा। यह भी कि एनटीए अपने संसाधनों का प्रयोग करके दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। साथ ही एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी की जवाबदेही स्वीकारी है। दरअसल, आरोप है कि नीट का पेपर 'क्वेश्चन बैंक' के जरिये लीक किया गया, जिसमें फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीन से ज्यादा सवाल थे। जिसमें आधे हूबहू परीक्षा में आए। आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिये ये प्रश्नपत्र लाखों तक पहुंचे। हालांकि, इस मामले का खुलासा सीकर से हुआ, लेकिन कहते हैं कि पेपर पहले केरल से एक मई को आया और उसके तार नासिक से लेकर उत्तराखंड तक जुड़े थे। एनटीए ने कहा है कि सात मई की रात एक व्हिसलब्लोअर से उन्हें पेपर लीक की सूचना मिली। बताते हैं कि सीकर के एक पीजी संचालक ने पेपर लीक की सूचना पुलिस को दी। कालांतर में पेपर से जुड़ी ऑनलाइन चैट वायरल हो गई। एनटीए द्वारा जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के बाद एक दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। यह विडंबना ही है कि भ्रष्टाचार के बाजार में लाखों छात्रों की मेहनत और सपने नीलाम हो रहे हैं। कुछ लोग लीक मामलों में राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लगा रहे हैं। तभी कई बार नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बावजूद किसी को बड़ी सजा अब तक नहीं मिली है। यही वजह कि नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की मांग की जा रही है क्योंकि पेन-पेपर मोड में पेपर लीक होने की ज्यादा आशंका रहती है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा को सुरक्षित व पारदर्शी बताया जा रहा है। साथ ही पारदर्शी जांच व जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। सवाल स्टाफ की आउटसोर्सिंग को लेकर भी उठे हैं। परीक्षाएं हाइब्रिड परीक्षा मॉडल के साथ ऑनलाइन कराने की भी मांग है।

प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर राजनीति कितनी जायज

> रिजर्व बैंक और कारोबारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत ने कुल 775 अरब डॉलर का आयात किया। इस आयात में सिर्फ चार प्रमुख वस्तुओं की हिस्सेदारी 240.7 अरब डॉलर रही। इसमें सबसे ज्यादा खर्च कच्चे तेल पर रहा। आंकड़ों के अनुसार, देश ने अकेले क्रूड ऑयल आयात पर ही करीब 134.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं।

भारतीय परंपरा में आभूषणों को सिर्फ पहनने या सौंदर्य बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता रहा है। भारतीय परिवारों के लिए सोना-चांदी आदि के गहने बुरे वक्त के लिए एक तरह से संचित निधि की भूमिका निभाते रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय परिवार शादी-विवाह के मौके पर सोने-चांदी के गहने खरीदने में दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। भारतीय गृहिणियों की कमजोरी और सौंदर्य का जरिया रहा यह सोना भी विवादों में आ गया है। इसकी वजह है, प्रधानमंत्री मोदी की अपील, जिसमें उन्होंने लोगों से एक साल तक के लिए सोने की गैरजरूरी खरीद को टालने की अपील की है। प्रधानमंत्री की इस अपील के अपने मायने हैं और जरूरत भी। अव्वल तो इस पर विपक्षी दलों का सहयोग मिलना चाहिए था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सरकार चलाने में नाकामी के चलते प्रधानमंत्री लोगों से यह खरीदो और यह ना खरीदो की अपील कर रहे हैं।प्रधानमंत्री के बयान के पीछे 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उपजे हालात हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर संकट उठ खड़ा हुआ है। चूंकि होमुर्ज जलडमरू मध्य पर ईरान का कब्जा है और अमेरिकी हमले के विरोध में उसने इसके जरिए सहज तरीके से आवाजाही पर रोक लगा रखी है, इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति का संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से जहां पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति महंगी हुई है, वहीं सोने की वैश्विक स्तर पर कीमतें लगातार बढ़ने से उसका भी आयात महंगा हुआ है। देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम पदार्थ ही हैं। इसके अलावा रासायनिक खादों बनाने के लिए भी पेट्रोलियम पदर्थों को ही कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैश्विक

सप्लाई कमजोर होने के चलते इन सबके आयात पर होने वाले भारी खर्च के चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इन दिनों लगातार कम होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की अपील इसी भंडार को बचाने के लिए भारत में सबसे ज्यादा आयात खर्च पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, सोना और रासायनिक उर्वरकों का है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में इन्हीं चार वस्तुओं के आयात पर करीब 240 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 20 लाख करोड़ से अधिक का खर्च किया है। जो देश के कुल आयात बिल का करीब एक तिहाई है। इसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। जो लगातार कम होता जा रहा है। एक मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.7 अरब डॉलर से घटकर महज 690 अरब अमरीकी डॉलर रह गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के मुताबिक, देश के स्वर्ण भंडार में भी कमी आई, जो पांच अरब डॉलर घटकर 115 अरब डॉलर हो गया। भारत की निधियों के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी इस सप्ताह में 2.7 अरब डॉलर घटकर 551 अरब डॉलर ही रह गई। इसी तरह देश का विशेष यानी ट्राजेक्शन अधिकार भी करीब 1.5 अरब डॉलर बढ़कर 18.78 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत जो आरक्षित आर्थिक भंडार है, उसमें भी गिरावट देखी गई, जो अस्सी लाख डॉलर बढ़कर 4.86 अरब डॉलर हो गई। वैसे तो वैश्विक संकट के चलते दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं हिचकोले खा रही हैं। भारत भी उसी में समाहित है। इसी से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने एक तरह से मितव्ययिता और खर्च घटाने की अपील की है।

रिजर्व बैंक और कारोबारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत ने कुल 775 अरब डॉलर का आयात किया। इस आयात में सिर्फ चार प्रमुख वस्तुओं की हिस्सेदारी 240.7 अरब डॉलर रही। इसमें सबसे ज्यादा खर्च कच्चे तेल पर रहा। आंकड़ों के अनुसार, देश ने अकेले क्रूड ऑयल आयात पर ही करीब 134.7 अरब डॉलर खर्च किए हैं। चूंकि पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से तेल की कीमतों में भारी उछाल दिख रहा है,। इसलिए भारत पर यह खर्च बढ़ गया है। अप्रैल में भारत ने औसतन 114.48 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चे तेल का आयात किया। इन कीमतों की तुलना पिछले साल की कीमतों से करें तो इसमें भारी उछाल दिखता है। पिछले वित्त वर्ष में देश ने औसतन 70.99 डॉलर प्रति बैरल की दर से आयात किया। भारत अपने खर्च के पेट्रोलियम पदार्थों का 88 फीसद हिस्सा आयात करता है। जाहिर है कि इस मद में भारत को हर साल अतिरिक्त आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और कार पूलिंग जैसी योजनाओं को अपनाने की लोगों से अपील की है।

भारतीय घरों, विशेषकर गृहिणियों के लिए सोना सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। हाल के वर्षों में चूंकि बैंकों में जमा धन पर खास कमाई नहीं हो रही है, उसकी तुलना में सोने में रिटर्न बढ़ रहा है। इस वजह से सोने की मांग में बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत ने दूसरे नंबर पर विदेशी मुद्रा सोने के आयात में ही खर्च की है। मौजूदा वर्ष में सोने का आयात रिकॉर्ड 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में करीब 24 प्रतिशत ज्यादा है। जाहिर है कि इस पर भी भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ रहा है। चूंकि भारत स्विटजरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात से सोना आयात करता है। इसलिए यहां विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में खर्च करनी पड़ती है। वैसे पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 4.7 प्रतिशत कम सोना आयात हुआ है। इसकी वजह वैश्विक स्तर पर बढ़ती इसकी कीमतें हैं। फिर भी सोने के प्रति भारतीयों का मोह कम नहीं हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री को सोने के गैर जरूरी खरीद को टालने के लिए अपील करनी पड़ी है।

भारत में जितना खाद्य तेल का इस्तेमाल होता है, उसका करीब 57 से 60 प्रतिशत तक का हिस्सा आयात करना पड़ता है। इस मद में भी भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में ही अब तक विदेशों से वनस्पति तेलों के आयात पर करीब 19.5 अरब डॉलर खर्च करना पड़ा है। चूंकि लोगों के खानपान पर रोक नहीं लगाई जा सकती, फिर खान-पान में कटौती का कसर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्षमता में गिरावट के रूप में नजर आ सकता है। जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा। इसलिए इस मद में हो रहे खर्च को रोकना आसान नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने खाद्य तेलों के खर्च में कटौती की बात सीधे तौर पर तो नहीं की है, लेकिन यह जरूर कहा है कि लोग खाद्य तेलों का सीमित उपयोग करें। इसी तरह रासायनिक उर्वरकों के आयात 77 प्रतिशत बढ़कर 14.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसलिए मोदी ने लोगों किसानों से रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल 50 प्रतिशत तक कम करने की अपील की है। उन्होंने किसानों को डीजल पंप की जगह सोलर पंप अपनाने की सलाह भी दी, ताकि पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता घटाई जा सके।

कारोबारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ इन्हीं चार चीजों का कुल आयात बिल पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार बढ़कर 112 अरब डॉलर से 240.7 अरब डॉलर हो गया है। इससे देश के सामने संकट होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री की अपील इसी संकट से बचाव का रास्ता है। याद कीजिए, पिछली सदी के साठ के दशक को, जब भारत में अपनी पूरी जनसंख्या को खिलाने भर के लिए अनाज का उत्पादन तक नहीं हो पाता था। तब अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ता था। अमेरिका इसके एवज में भारत को आंख दिखाता था। इससे बचाव के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से एक शाम उपवास की अपील की थी। वे खुद भी सोमवार की शाम को उपवास रखते थे। इसके बाद ही उन्होंने कृषि क्रांति का सपना देखा। तब प्रधानमंत्री का लोगों ने साथ दिया था, विपक्षी दल चाहे तब जिस भी स्थिति में रहे हों, उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाए थे।

प्रेरणा

संतोष की दौलत सबसे बड़ी

आज की दुनिया में सफलता को अक्सर पैसे, बड़े घर, महंगी गाड़ियों और ऊंचे पदों से मापा जाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है। किसी को अधिक पैसा चाहिए, किसी को ज्यादा पहचान, तो किसी को दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी। इस भागती हुई दुनिया में इंसान धीरे-धीरे यह भूलता जा रहा है कि असली खुशी आखिर कहां छिपी है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। ऐसे समय में संतोष का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि संतोष ही वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से स्थिर और खुश बनाती है।

महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। दुनिया उन्हें असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति मानती थी। उन्होंने विज्ञान को नई दिशा दी, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाया और पूरी दुनिया में सम्मान पाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता केवल उनका ज्ञान नहीं था, बल्कि उनकी सादगी और संतोष था। उनके पास प्रसिद्धि थी, धन था, सम्मान था, फिर भी वे दिखावे और लालच से दूर रहते थे। उनका कमरा साधारण था, जीवन सरल था और चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी।

एक बार एक अमीर उद्योगपति उनसे मिलने आया। वह हैरान था कि इतना बड़ा वैज्ञानिक होकर भी आइंस्टीन विलासिता भरा जीवन क्यों नहीं जीते। उसने उनसे कहा कि अगर वे चाहें तो अपनी प्रसिद्धि से कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आज के समय में शायद अधिकतर लोग यही करते भी। लेकिन आइंस्टीन ने उसे कोई लंबा भाषण नहीं दिया। वे उसे खिड़की के पास ले गए और बाहर खेल रहे एक बच्चे की ओर इशारा किया। वह बच्चा पतंग उड़ा रहा था। हवा कभी पतंग को ऊपर ले जाती, कभी नीचे गिरा देती, लेकिन बच्चा हर स्थिति में हंस रहा था। उसके चेहरे पर आनंद था, क्योंकि वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह केवल उस पल को जी रहा था।

आइंस्टीन ने उद्योगपति से कहा कि जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इंसान यदि हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहे, हर समय और ज्यादा पाने की इच्छा करे, तो वह जीने का आनंद खो देता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे या सपने देखना बंद कर दे। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे पास है, उसकी कीमत समझी जाए। जब इंसान केवल कमी पर ध्यान देता है, तब उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन जब वह अपने जीवन में मौजूद छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करने लगता है, तब उसके भीतर सच्चा आनंद जन्म लेता है।

आज अधिकांश लोग तुलना में जी रहे हैं। किसी के पास नई गाड़ी आई तो दूसरा बेचैन हो जाता है। किसी को बड़ी नौकरी मिली तो दूसरों को अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की चमकती तस्वीरें देखकर यह मान लेते हैं कि सामने वाला पूरी तरह खुश है, जबकि वास्तविकता अक्सर अलग होती है। इस निरंतर तुलना ने इंसान से उसका संतोष छीन लिया है। वह जितना पाता है, उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। यह इच्छा कभी समाप्त नहीं होती।

संतोष जीवन को ठहराव नहीं देता, बल्कि संतुलन देता है। यह इंसान को लालच से बचाता है और उसे मानसिक शांति देता है। जिस व्यक्ति के भीतर संतोष होता है, वह छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है। उसे प्रकृति की सुंदरता अच्छी लगती है, परिवार के साथ बिताया समय अनमोल लगता है और साधारण क्षण भी उसे आनंद देते हैं। दूसरी ओर, असंतोष से भरा व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है। उसके पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, उसे हमेशा कुछ अधूरा महसूस होता है।

हमारे समाज में अक्सर यह सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब सबसे आगे निकलना है। लेकिन असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से तय नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन उसके मन में शांति नहीं, तो वह भीतर से गरीब ही है। वहीं एक साधारण व्यक्ति, जिसके पास सीमित साधन हैं लेकिन मन में संतोष है, वह वास्तव में समृद्ध है। संतोष मन की वह अवस्था है जहां इंसान अपने जीवन को स्वीकार करना सीखता है। वह यह समझता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, फिर भी जीवन सुंदर हो सकता है।

प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सूरज हर दिन बिना किसी शिकायत के उगता है। पेड़ बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं। नदी लगातार बहती रहती है, क्योंकि उसका आनंद बहने में है, सब कुछ रोककर रखने में नहीं। इंसान जब प्रकृति से दूर हुआ, तब वह संतोष से भी दूर हो गया। उसने जरूरतों को इच्छाओं में और इच्छाओं को लालच में बदल दिया। परिणाम यह हुआ कि बाहरी चमक बढ़ती गई लेकिन भीतर का सुकून कम होता गया।

संतोष का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान अपने सपनों को छोड़ दे। बल्कि संतोष हमें यह सिखाता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भी मन की शांति को न खोया जाए। मेहनत कीजिए, सपने देखिए, आगे बढ़िए, लेकिन अपने आनंद को केवल परिणाम पर मत टिकाइए। क्योंकि यदि खुशी हमेशा भविष्य में टलती रहेगी, तो वर्तमान कभी सुंदर नहीं लगेगा।

जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अंत में मायने यह नहीं रखता कि हमारे पास कितना धन था, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने कितना सुकून महसूस किया, कितने प्रेम से जिया और कितनी मुस्कानें बांटीं। संतोष वही कला है जो इंसान को यह एहसास कराती है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। आइंस्टीन की बात आज भी उतनी ही गहरी लगती है—ज्ञान इंसान को महान बना सकता है, लेकिन संतोष ही उसे सच में खुश रखता है। जिंदगी का असली आनंद सब कुछ हासिल कर लेने में नहीं, बल्कि जो जरूरी नहीं है उसे छोड़कर भी मुस्कुराने में है। जब इंसान यह सीख जाता है, तभी वह वास्तव में जीना शुरू करता है।

पीएम मोदी के राष्ट्रहित के आह्वान में भी राजनीति क्यों?

आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं ने मानव सभ्यता को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। खाड़ी देशों में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और युद्ध की विभीषिका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे तक प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं का बाधित होना, डॉलर के मुकाबले विभिन्न देशों की मुद्राओं का कमजोर होना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न असंतुलन ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और सोने का भी विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने की खरीद को सीमित करने का आह्वान केवल एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किया गया दूरदर्शी चिंतन है। दुर्भाग्य यह है कि मोदी की मितव्ययिता की अपील पर पूरे देश को एकजुट होकर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, उस विषय को भी राजनीतिक विवाद का हथियार बना दिया गया। कुछ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की इस अपील को जनता में भय फैलाने वाला कदम बताया, तो कुछ ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास कहा। जबकि वस्तुतः यह अपील राष्ट्र को भविष्य की संभावित चुनौतियों के प्रति सचेत करने और समय रहते आत्मानुशासन अपनाने का संदेश है। यह राजनीति का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी का प्रश्न है। जब विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र आर्थिक संकटों से जूझ रहे हों, तब भारत के प्रधानमंत्री यदि नागरिकों को संयम एवं मितव्ययिता का सूत्र देते हैं तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह पहला अवसर नहीं है, जब प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की को बनाए रखने की सामूहिक चिन्ता करते हुए मितव्ययिता एवं संयम की अपील की हो। भारत की संस्कृति मूलतः संयम प्रधान रही है। भारतीय जीवन-दर्शन में संयम को केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। हमारे ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने सदैव आवश्यकता और विलासिता के बीच अंतर करना सिखाया। महावीर, बुद्ध, गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने त्याग और संयम को ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भारतीय संस्कृति कहती है कि जितना आवश्यक हो उतना ही उपभोग करो, क्योंकि असीमित उपभोग अंततः संकट को जन्म देता है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों तक टिकाऊ और संतुलित बनी रही। आज जब पूरी दुनिया उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम भुगत रही है, तब भारत की यही संयम आधारित संस्कृति समाधान का मार्ग दिखा सकती है। सोने के प्रति भारतीय समाज का आकर्षण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरा रहा है। विवाह, पारिवारिक उत्सव, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक प्रतिष्ठा में सोने का विशेष स्थान है। लेकिन यह भी एक कठोर सत्य है कि भारत का अधिकांश सोना आयातित होता है। हर वर्ष अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सोने के आयात पर खर्च होता है। यह सोना उत्पादन या औद्योगिक विकास में उपयोग होने के बजाय घरों और लॉकरों में बंद होकर निष्क्रिय पड़ा रहता है। ऐसे समय में जब विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा हो और रुपये की कीमत लगातार गिर रही हो, तब सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। यह किसी की परंपराओं के विरोध में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती के पक्ष में उठाया गया कदम है।

इसी प्रकार ईंधन के उपयोग में संयम भी समय की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ता है। यदि नागरिक ईंधन के अनावश्यक उपयोग को सीमित करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, ऊर्जा बचत को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। संयम का अर्थ केवल त्याग नहीं होता, बल्कि दूरदर्शिता और जिम्मेदारी भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील इसी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। उन्होंने किसी प्रकार की जबरदस्ती या प्रतिबंध की बात नहीं की, बल्कि नागरिकों से स्वैच्छिक सहयोग की अपेक्षा की। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व की पहचान है।

एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का कर्तव्य केवल संकट आने पर कदम उठाना नहीं होता, बल्कि संकट के संकेतों को पहचानकर समय रहते जनता को तैयार करना भी होता है। आज जब दुनिया के कई देशों में आर्थिक अस्थिरता के कारण भारी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव देखने को मिल रहे हैं, तब भारत अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में अपनाई गई आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति का परिणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वव्यापी संकटों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। महामारी से लेकर युद्धजनित परिस्थितियों तक भारत सरकार ने लगातार राहत योजनाएं चलाईं, गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, किसानों और मध्यम वर्ग को विभिन्न प्रकार की सहायता दी तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए।

अभियान

बाबा बैद्यनाथ धाम: जहां एक साथ बसते हैं शिव और शक्ति के दिव्य स्वरूप

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भगवान शिव का स्थान अत्यंत अद्वितीय और रहस्यमय माना गया है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि और अंत के प्रतीक हैं। वे संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। उनकी पूजा में जहां वैराग्य का भाव दिखाई देता है, वहीं भक्ति और प्रेम की गहराई भी झलकती है। देशभर में भगवान शिव के अनगिनत मंदिर मौजूद हैं, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अलग माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इन बारह ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इन्हीं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा पवित्र धाम भी है, जिसका महत्व केवल ज्योतिर्लिंग होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। यह पावन स्थान है झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम।

बाबा बैद्यनाथ धाम को विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जहां ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी स्थित है। यही कारण है कि इस धाम की महिमा अन्य सभी शिवधामों से अलग और विशेष मानी जाती है। यहां भगवान शिव के साथ मां शक्ति का भी निवास है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो उठे। वे माता सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। भगवान शिव के इस विकराल रूप से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए, जो पृथ्वी के अलग-अलग स्थानों पर गिरे। जहां-जहां माता सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि देवघर में माता सती का हृदय गिरा था। इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में भी पूजित हुआ।

देवघर का अर्थ ही होता है "देवताओं का घर"। इस पवित्र नगरी में शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त स्वरूप भक्तों को दिखाई देता है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु केवल भगवान शिव की आराधना ही नहीं करता, बल्कि मां पार्वती के दर्शन कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना भी करता है। यही वजह है कि बाबा बैद्यनाथ धाम को "कामना ज्योतिर्लिंग" भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है।

बाबा बैद्यनाथ धाम का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तब रावण ने उनसे लंका चलने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा कि यदि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर रखा गया, तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला, लेकिन देवताओं ने उसकी योजना को विफल करने के लिए एक युक्ति बनाई। मार्ग में रावण को लघुशंका के लिए रुकना पड़ा और उसने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया। लेकिन वह अधिक देर तक उसे संभाल नहीं पाया और उसने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। उसी क्षण शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। यही स्थान आगे चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम कहलाया।

इस कथा के कारण भी इस धाम की महिमा और बढ़ जाती है। भक्त मानते हैं कि यहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं और अपने भक्तों की हर पीड़ा दूर करते हैं। श्रावण मास में इस धाम का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। देशभर से लाखों कांवड़िए गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करने पहुंचते हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक की यह कठिन यात्रा केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण की जीवंत मिसाल भी है। "बोल बम" और "हर हर महादेव" के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है।

बाबा बैद्यनाथ धाम की वास्तुकला भी अत्यंत आकर्षक और प्राचीन है। मंदिर परिसर में मुख्य ज्योतिर्लिंग के साथ कई अन्य देवी-देवताओं के मंदिर स्थित हैं। यहां मां पार्वती का मंदिर विशेष रूप से भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। एक विशेष बात यह भी मानी जाती है कि बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती के मंदिर को एक पवित्र धागे से जोड़ा गया है, जो शिव और शक्ति के अखंड संबंध का प्रतीक है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस दर्शन को भी दर्शाता है, जिसमें शिव और शक्ति को एक-दूसरे के बिना अधूरा माना गया है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिव और शक्ति सृष्टि के दो मूल तत्व हैं। शिव चेतना के प्रतीक हैं, जबकि शक्ति ऊर्जा का स्वरूप मानी जाती हैं। शिव बिना शक्ति के शून्य हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में दोनों की संयुक्त आराधना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। देवघर का यह पवित्र धाम इसी दिव्य मिलन का जीवंत प्रतीक है। यहां आने वाले भक्त केवल पूजा नहीं करते, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जो मन को गहरी शांति प्रदान करती है।

कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति, विवाह, स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति के लिए लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। कई भक्त वर्षों तक लगातार यहां आकर जलाभिषेक करते हैं और अपनी आस्था को भगवान शिव और मां शक्ति के चरणों में समर्पित करते हैं। इस धाम का वातावरण इतना दिव्य माना जाता है कि यहां पहुंचते ही मन में एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है।

धार्मिक महत्व के साथ-साथ बाबा बैद्यनाथ धाम भारतीय संस्कृति और आस्था का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां केवल भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में दिन-रात पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार का क्रम चलता रहता है। सावन और महाशिवरात्रि के समय यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। उस समय पूरा देवघर शिवमय हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं कैलाश पृथ्वी पर उतर आया हो। आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में भी बाबा बैद्यनाथ धाम लोगों के लिए आस्था, विश्वास और मानसिक शांति का केंद्र बना हुआ है। यहां आने वाले भक्त केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की थकान और तनाव को भी भगवान शिव के चरणों में छोड़ आते हैं। यही कारण है कि यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास का प्रतीक बन चुका है।

बाबा बैद्यनाथ धाम हमें यह संदेश भी देता है कि जीवन में संतुलन और समरसता कितनी आवश्यक है। शिव और शक्ति का एक साथ विराजमान होना इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का संचालन केवल शक्ति या केवल चेतना से नहीं, बल्कि दोनों के संतुलन से संभव है। यही संतुलन जीवन को पूर्णता देता है। देवघर की पवित्र धरती पर स्थित यह दिव्य धाम सदियों से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। यहां की घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और भक्तों की आस्था हर व्यक्ति के मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां भक्त शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि यह धाम विश्वभर में अद्वितीय और पूजनीय माना जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात में टेंडर कोकोनट का उत्पादन पिछले दो वर्ष में 20 प्रतिशत बढ़ा, राज्य में वार्षिक 26 करोड़ नारियल का उत्पादन होता है

▸▸ गुजरात सरकार के प्रोत्साहन तथा जागरूकता कार्यक्रमों से राज्य में खेती की तसवीर बदली

▸▸ गिर के युवा किसान दिनेश सोलंकी ने अनूठे प्रयोग से नारियल उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि की, आय 12-15 लाख रुपए तक पहुँची

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का कृषि क्षेत्र परंपरागत खेती से आधुनिक, टेक्नोलॉजी आधारित तथा निर्यातोन्मुखी खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात में भी परंपरागत फसलों के अलावा बागवानी फसलों तथा मूल्यवर्धित खेती को निरंतर प्रोत्साहन मिलने से किसानों की आय बढ़ी है। राज्य का विशाल समुद्री तट नारियल की खेती के लिए अनुकूल होने के कारण उसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। टेंडर कोकोनट की बढ़ती मांग तथा समुद्री तट के विस्तार के कारण गुजरात ने नारियल की खेती में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज कराया है।

गुजरात में पिछले 2 वर्ष में टेंडर कोकोनट का उत्पादन लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा

पिछले 2 वर्ष में राज्य में टेंडर कोकोनट के उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज किसान वार्षिक लगभग 26 करोड़ नारियल का उत्पादन करते हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि गुजरात बागवानी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। राज्य के लगभग 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती की जाती है; जिसमें गिर सोमनाथ, जूनागढ़, भावनगर, वलसाड, नवसारी, कच्छ तथा देवभूमि द्वारका जिलों का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2024-25 के आँकड़ों के अनुसार राज्य में टेंडर कोकोनट की औसत उत्पादकता लगभग 9.26 हजार प्रति हेक्टेयर है।

किसानों को राज्य सरकार दे रही है 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी

राज्य के किसान बागवानी फसलों तथा मूल्यवर्धन की ओर मुड़ें; इसके लिए गुजरात सरकार के बागवानी विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही; किसानों पर आर्थिक बोझ न आए; इसके लिए नारियल की बुवाई पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त; मल्चिंग तथा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी पद्धतियों के उपयोग से फसल की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिले; इस उद्देश्य से उसमें भी सहायता दी जाती है। इसी प्रकार; बागवानी विभाग के अधीनस्थ नर्सरी से नारियल की ऊँची किस्म, वामन किस्म तथा हाइब्रिड किस्मों के अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे मिल जाते हैं और गुजरात ग्रीन रिवॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा टपक सिंचाई पद्धति में सहायता दी जाती है।

नारियल के लिए हानिकारक रगोस व्हाइटफ्लाई का नाश करने के लिए गिर के किसान ने अनूठा प्रयोग किया

चोरवाड से उना तक का समुद्र तटवर्ती क्षेत्र 'लीली नाघेर' (हरियाले क्षेत्र) के रूप में जाना जाता है, जहाँ पिछले दो वर्ष में रोगस व्हाइटफ्लाई (रोगस सफेद मक्खी) के प्रकोप से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यद्यपि; गुजरात सरकार के मार्गदर्शन व किसानों के प्रयासों से स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाडा के युवा किसान दिनेश सोलंकी ने इस समस्या के निवारण के लिए देसी उपाय आजमाकर नारियल के उत्पादन के साथ अपनी आय में भी वृद्धि की है। उन्होंने 1000 लीटर पानी में गुड़ तथा गिर गाय के दूध का मिश्रण करके व्हाइटफ्लाई को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है।

पहले उनके खेत में वर्ष में केवल 1,000 से 1,500 नारियल का उत्पादन होता था, परंतु इस प्रयोग के बाद यह उत्पादन बढ़कर वार्षिक 8,000 से 10,000 नारियल के करीब दर्ज हुआ है। आज उनकी वार्षिक आय 12 से 15 लाख रुपए तक पहुँची है और उनकी सफलता देखकर अन्य किसान भी यह पद्धति अपनाने को प्रेरित हुए हैं।

नारियल की खेती का क्षेत्र 70,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का गुजरात सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार का आगामी वर्षों में नारियल बुवाई क्षेत्र 70,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। साथ ही; वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोनट पाउडर जैसे नारियल आधारित उत्पादों तथा प्रोसेसिंग द्वारा उनके मूल्यवर्धन एवं निर्यात बाजारों में प्रवेश के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। इसके चलते गुजरात आगामी समय में नारियल आधारित उद्योगों के वैश्विक हब के रूप में उभर आएगा।

भीषण गर्मी में यात्रियों को राहत: भावनगर मंडल के नवागढ स्टेशन पर नि:शुल्क शीतल पेयजल का वितरण

भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान के मद्देनज़र यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जनहित में विशेष पहल की गई है। इस क्रम में दिनांक 13 मई, 2026 (बुधवार) को नवागढ रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण की व्यवस्था की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि नवागढ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्षेत्र में यात्रियों को निःशुल्क शीतल पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से काफी राहत मिली।

निःशुल्क शीतल पेयजल वितरण में "मोजिला गणेश बापा ग्रुप-जेतपुर" का सहयोग रहा। इस संस्था के सदस्यों द्वारा यात्रियों के बीच 1000 ठंडा पानी की बोतल वितरित की गई।

स्टेशन पर इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने में भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा वितरण कार्य को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न किया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) श्री दिनेश वर्मा ने कहा, "भीषण गर्मी के दौरान यात्रियों को राहत प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनगर मंडल द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से इस प्रकार की जनहितकारी गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह पहल हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता एवं यात्री-हित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।"

भावनगर मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं मानवीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती रहें। भीषण गर्मी के दौरान इस प्रकार की राहत सेवाएँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय द्वारा प्रतापनगर–एकतानगर खंड एवं वडोदरा तथा प्रतापनगर स्टेशन का निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय द्वारा आज प्रतापनगर–एकतानगर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वडोदरा एवं प्रतापनगर स्टेशन का निरीक्षण भी किया।

महाप्रबंधक श्री पाण्डेय ने मंडल रेल प्रबंधक वडोदरा मंडल श्री राजू भडके तथा RLDA एवं NHSRCL के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वडोदरा स्टेशन का दौरा किया। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने उन्हें यार्ड रीमॉडलिंग परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अवसंरचना कार्यों के बारे में जानकारी दी, जिसमें लाइन संख्या 6 एवं 7 को मुख्य लाइन से सीधे जोड़ने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म संख्या 4 एवं 5 की क्षमता में वृद्धि, एक नई स्टेबलिंग लाइन का विकास तथा अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन के अंतर्गत डिलांज का उद्घाटन भी किया गया।

महाप्रबंधक ने वडोदरा स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड का निरीक्षण मंडल प्रबंधक तथा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया, निरीक्षण के दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक लोको शेड में किए गए संशोधनों एवं भविष्य की विस्तार योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, अपने दौरे के दौरान उन्होंने शेड के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया, जिसमें न्यूमैटिक सेक्शन, ऑक्सिलियरी मोटर सेक्शन तथा बोगी सेक्शन शामिल हैं।

उन्हें लोको विफलताओं को शून्य करने के उद्देश्य से किए जा रहे तकनीकी विश्लेषण एवं अपनाए जा रहे सुधारात्मक उपायों के संबंध में भी अवगत कराया गया। इसके बाद महाप्रबंधक ने शेड में विकसित इन-हाउस ड्यूल मोड शंटिंग इंजन 'सारथी' का निरीक्षण किया तथा लोको शेड द्वारा की गई इस पहल की सराहना की। यह शंटिंग इंजन ओएचई तथा बैटरी — दोनों मोड में कार्य करने में सक्षम है, जिससे शंटिंग कार्यों में सुगमता, समय की बचत तथा 2–3 लोकोमोटिवों की कैस्केडिंग की आवश्यकता समाप्त होने जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। उन्हें इलेक्ट्रिक लोको शेड में स्थापित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई।

निरीक्षण के अगले चरण में महाप्रबंधक ने प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं, स्टेशन विकास कार्यों, यार्ड लेआउट तथा निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज की प्रगति का जायजा लिया और कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने प्रतापनगर रेलवे कॉलोनी स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नव निर्मित पिकलबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया।

प्रतापनगर - एकतानगर खंड के विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के बाद एकता नगर स्टेशन पर पहुंचने पर वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने महाप्रबंधक को स्टेच्यू आफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों के लिए एकतानगर स्टेशन को और विकसित करने की योजना से अवगत कराया। ट्रेन परिचालन क्षमता को विस्तार देते हुए एकता नगर स्टेशन पर एक अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण प्रस्तावित है तथा नान फेयर रिवेन्यू के तहत फूड प्लाजा प्रस्तावित है।

एकतानगर स्टेशन से अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन के लिए लाइन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रतापनगर - एकतानगर खंड के तिलकवाड़ा और मोरया स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। प्रतापनगर - एकतानगर रेल खंड में ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में सुधार हेतु मेटलफेसिंग भी लगाई गई है।

पुरी स्टेशन पर ब्लॉक के चलते गांधीधाम-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस आंशिक निरस्त

पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण गांधीधाम-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनें आंशिक निरस्त रहेगी। विवरण निम्नानुसार है:

आंशिक निरस्त ट्रेनें

▸▸ 15,22 एवं 29 मई 2026 की ट्रेन संख्या 12993 गांधीधाम–पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

▸▸ 18 एवं 25 मई 2026 की ट्रेन संख्या 12994 पुरी–गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

▸▸ 20 एवं 27 मई 2026 की ट्रेन संख्या 22973 गांधीधाम–पुरी एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

▸▸ 23 एवं 30 मई 2026 की ट्रेन संख्या 22974 पुरी–गांधीधाम एक्सप्रेस मालतीपाटपुर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

यात्रियों से अनुरोध है उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की अधिकृत वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की गुजरात को विशिष्ट भेंट

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

▸▸ भारत का पहला सेमी हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट गुजरात को मिलना पूरे राज्य के लिए गौरव की बात : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ धोलेरा एसआईआर, निर्माणाधीन धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के बीच तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले इस बहुआयामी प्रोजेक्ट से ईंधन की बचत होगी तथा कार्बन उत्सर्जन और लॉजिस्टिक्स खर्च में कमी आएगी

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत वाले अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा तक सेमी हाईस्पीड डबल लाइन रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात को पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किए गए इस विशिष्ट प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण विकासोन्मुखी भेंट देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करने वाला और स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय रेलवे का यह प्रथम सेमी हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट अहमदाबाद, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर), निर्माणाधीन धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के बीच तेज कनेक्टिविटी देने वाला एक बहुआयामी प्रोजेक्ट होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का पहला सेमी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट गुजरात को मिलना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री के विजन से शुरू होने वाला यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गुजरात के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। देश के पहले सेमी हाईस्पीड रेल प्रोजेक्ट के रूप में, यह प्रोजेक्ट सेमी हाईस्पीड रेल के चरणबद्ध विस्तार के लिए एक संदर्भ मॉडल के रूप में काम करने वाले एक अग्रणी प्रोजेक्ट के रूप में सेवाएं देगा।

केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए इस प्रोजेक्ट में एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह प्रोजेक्ट लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह प्रस्तावित प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 134 किमी की वृद्धि करेगा। इसके अलावा, 284 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

इतना ही नहीं, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन व्यवस्था के हिस्से के रूप में यह प्रोजेक्ट ईंधन बचाएगा तथा कार्बन उत्सर्जन और लॉजिस्टिक्स खर्च को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा मई दिवस के अवसर पर रेलवे कर्मचारियों का सम्मान

समर्पित सेवा के लिए 38 व्यक्तिगत पुरस्कार एवं एक समूह नकद पुरस्कार प्रदान किए गए

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पाण्डेय कार्यकारी समिति की सदस्याओं के साथ पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित मई दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार विजेता कर्मचारी को सम्मानित करते हुए।

पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO) द्वारा मई दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम रेलवे पर रेल सेवाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने हेतु निष्ठा एवं अथक परिश्रम से कठिन दायित्व निभाने वाले रेलवे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम विभिन्न विभागों के उन कर्मचारियों के समर्पण एवं प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जो यात्रियों की सुविधा तथा रेलवे परिचालन के हित में निरंतर कार्यरत हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता पाण्डेय ने कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों, कारखानों एवं विभागों के कर्मचारियों को समारोह के दौरान सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट योगदान एवं समर्पित सेवा के लिए कुल 38 व्यक्तिगत पुरस्कार तथा एक समूह नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा मेरिट प्रमाणपत्र एवं उपहार भेंट किए गए।

श्रीमती सुजाता पाण्डेय ने समारोह को संबोधित करते हुए कर्मचारियों के ईमानदार प्रयासों, अनुशासन एवं समर्पण की सराहना की, जो चुनौतीपूर्ण एवं गतिशील कार्य परिस्थितियों के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं कठिन परिश्रम निर्बाध रेल सेवाओं को बनाए रखने तथा यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सेवाएं प्रदान कर रही महिला कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान की भी प्रशंसा की।

श्रीमती पाण्डेय ने आगे कहा कि समर्पित सेवा के इस प्रकार के सम्मान युवा कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत एवं उत्कृष्टता का मानदंड सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करने से उनका मनोबल बढ़ता है तथा अन्य कर्मचारियों को भी अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती है।

इस अवसर पर श्रीमती पाण्डेय ने आगामी छह महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्वस्थ, सुखद एवं आनंदमय सेवानिवृत्त जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दीं तथा वर्षों से पश्चिम रेलवे की प्रगति एवं विकास में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

भारत की पहली Semi High-Speed Rail Project को मिली मंजूरी, कैबिनेट ने अहमदाबाद–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को दी मंजूरी

20,667 करोड़ की लागत से विकसित होगी भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना

नई दिल्ली / अहमदाबाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आज रेल मंत्रालय की अहमदाबाद (सरखेज) – धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। लगभग 20,667 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना होगी।

करीब 134 किलोमीटर लंबी यह नई रेलवे लाइन अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR), आगामी धोलेरा एयरपोर्ट तथा लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex) को अत्याधुनिक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना के पूर्ण होने के बाद अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे यात्रियों के लिए दैनिक आवागमन और एक ही दिन में आने-जाने की सुविधा अधिक सहज एवं आरामदायक बनेगी।

रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर कहा:

"अहमदाबाद–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना भारत के रेलवे इतिहास में एक नई शुरुआत है। यह केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि 'न्यू इंडिया' की आधुनिक, तेज और आत्मनिर्भर परिवहन व्यवस्था का प्रतीक है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित यह परियोजना आने वाले वर्षों में देशभर में सेमी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विस्तार का आधार बनेगी।"

अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) वेद प्रकाश ने कहा कि यह परियोजना गुजरात के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा: "यह परियोजना अहमदाबाद एवं धोलेरा क्षेत्र को विश्वस्तरीय रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा लाभ होगा। इस इस परियोजना से धोलेरा और अहमदाबाद की दूरी 1 घंटे से भी काम हो जाएगी और धोलेरा सीधे अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ जाएगी।

परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक दक्षता को मजबूत करना है। इस परियोजना से लगभग 284 गांवों एवं लगभग 5 लाख आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

भारतीय रेलवे के अनुसार यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे लगभग 0.48 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी तथा लगभग 2 करोड़ किलोग्राम CO उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 10 लाख पेड़ों के रोपण के बराबर पर्यावरणीय लाभ के समान है।

परियोजना को वर्ष 2030-31 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भावनगर मंडल के सतर्क लोको पायलट ने 6 सिंहों के झुंड को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया

पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल द्वारा एशियाई सिंहों एवं अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मंडल प्रशासन के निर्देशानुसार लोको पायलट निर्धारित गति सीमा का पालन करते हुए अत्यंत सतर्कता के साथ ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। लोको पायलटों की सजगता तथा वन विभाग के फॉरेस्ट ट्रैकरों के साथ समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 159, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 129 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल माह से अब तक 11 सिंहों को सुरक्षित बचाया जा चुका है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12 मई 2026 (मंगलवार) को लोको पायलट श्री रमेश पी. (मुख्यालय-जूनागढ़) तथा सहायक लोको पायलट श्री चिंतन कुमार (मुख्यालय-जूनागढ़) ट्रेन संख्या 52946 जूनागढ़–वेरावल पैसेंजर का संचालन कर रहे थे। इस दौरान जूनागढ़–विसावदर रेलखंड में किलोमीटर संख्या 05/01 के निकट रेलवे ट्रैक पर अचानक 6 सिंहों का एक झुंड पटरी पार करता दिखाई दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोको पायलट ने तत्काल सूझबूझ एवं तत्परता का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित रूप से रोक दिया, जिससे सभी सिंह संभावित दुर्घटना से बच गए।

इसके पश्चात लोको पायलट द्वारा ट्रेन मैनेजर (गार्ड) श्री ललन कुमार (मुख्यालय-जूनागढ़) को तत्काल सूचना दी गई। वन विभाग के फॉरेस्ट ट्रैकर ने मौके पर पहुंचकर सभी सिंहों को सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक से हटाया। स्थिति सामान्य होने के उपरांत लोको पायलट को ट्रेन के पुनः प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई तथा ट्रेन को सावधानीपूर्वक गंतव्य की ओर रवाना किया गया।

इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा सहित मंडल के अन्य अधिकारियों ने लोको पायलटों की सतर्कता, संवेदनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की।

भावनगर मंडल वन्यजीव संरक्षण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा रेलवे एवं वन विभाग के समन्वित प्रयासों से एशियाई सिंहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा।

तेल के डिब्बे हुए छोटे, जेब पर बोझ बड़ा: गुजरात में 'श्रिंकफ्लेशन' को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला

सूरत। गुजरात में लगातार बढ़ती महंगाई और खाने के तेल की घटती पैकेजिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दर्शनकुमार ए. नायक ने राज्य सरकार पर उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बाजार में खाने के तेल को लेकर "श्रिंकफ्लेशन" का खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां और व्यापारिक समूह पैकेजिंग का वजन कम करके आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, जबकि कीमतों में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा रही। कांग्रेस ने इसे सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक अन्याय और बाजार में पारदर्शिता की कमी बताया है।

दर्शनकुमार नायक ने कहा कि गुजरात देश के सबसे बड़े तिलहन उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। राज्य में बड़े पैमाने पर मूंगफली और कपास की खेती होती है, जिसके कारण यहां खाद्य तेल उत्पादन की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। इसके बावजूद आम लोगों को महंगे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में उत्पादन भरपूर हो रहा है तो फिर बाजार में तेल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम परिवार पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है और अब तेल कंपनियों द्वारा पैकेजिंग घटाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का स्वागत किया जिसमें लोगों से स्वास्थ्य और आयात खर्च कम करने के लिए खाने के तेल का सीमित उपयोग करने की बात कही गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह अपील देशहित और स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक है, लेकिन दूसरी ओर बाजार में जिस तरह से "श्रिंकफ्लेशन" का प्रयोग हो रहा है, वह उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कंपनियां पैकेजिंग का वजन कम कर रही हैं, लेकिन कीमतें लगभग पहले जैसी ही रखी जा रही हैं, जिससे ग्राहक बिना जानकारी के अधिक कीमत चुका रहा है।

दर्शनकुमार नायक ने कहा कि कुछ वर्षों पहले तक खाने का तेल आमतौर पर 15 किलो या 15 लीटर के डिब्बों में मिलता था। लेकिन अब अधिकतर कंपनियों ने पैकेजिंग को घटाकर 12.5 किलो, 13 किलो या 13 लीटर कर दिया है। बाजार में पैकेट और डिब्बों का आकार देखने में लगभग पहले जैसा ही रखा गया है, जिससे आम ग्राहक आसानी से यह समझ नहीं पाता कि वास्तविक मात्रा कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह तरीका उपभोक्ताओं के साथ पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ है और इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में वर्ष 2025-26 के दौरान मूंगफली उत्पादन 46 से

66 लाख मीट्रिक टन के बीच दर्ज किया गया है, जो देश के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक माना जा रहा है। इसके बावजूद बाजार में मूंगफली तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार मूंगफली तेल के एक कैन की कीमत 2341 रुपये से बढ़कर 2719 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह कपास उत्पादन भी लगभग 92.48 लाख गांठ तक दर्ज किया गया है, लेकिन खाद्य तेल बाजार में इसका लाभ आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद कीमतों में राहत नहीं मिलना यह दर्शाता है कि बाजार में कहीं न कहीं जमाखोरी, कृत्रिम कमी या व्यापारिक गठजोड़ जैसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं।

दर्शनकुमार नायक ने सरकार से कई सीधे सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि 15 किलो और 15 लीटर की पैकेजिंग को घटाकर 12.5 और 13 किलो/लीटर करने की अनुमति किस विभाग या प्राधिकरण ने दी। क्या लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी। यदि पैकेजिंग कम की गई है तो उसी अनुपात में कीमतों में कमी क्यों नहीं लाई गई। उन्होंने कहा कि आम ग्राहक को यह जानने का अधिकार है कि वह जिस कीमत पर सामान खरीद रहा है, उसकी वास्तविक मात्रा कितनी है और प्रति किलो या प्रति लीटर उसे कितना भुगतान करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान स्थिति में उपभोक्ता धीरे-धीरे आर्थिक नुकसान झेल रहा है, लेकिन बाजार व्यवस्था इतनी जटिल बना दी गई है कि सामान्य व्यक्ति इस बदलाव को तुरंत समझ नहीं पाता। उन्होंने कहा कि यही "श्रिंकफ्लेशन" की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें उत्पाद का आकार छोटा कर दिया जाता है लेकिन कीमत लगभग समान रखी जाती है। इससे कंपनियां अपने मुनाफे को सुरक्षित रखती हैं और ग्राहक को वास्तविक बढ़ी हुई कीमत का एहसास भी नहीं हो पाता।

कांग्रेस नेता ने मांग की कि राज्य सरकार इस पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन करे। उन्होंने कहा कि तेल मिलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां छापेमारी कर यह जांच की जानी चाहिए कि कहीं कृत्रिम रूप से स्टॉक रोककर कीमतें तो नहीं बढ़ाई जा रहीं। साथ ही यदि किसी प्रकार की कार्टेलाइजेशन या जमाखोरी सामने आती है तो संबंधित कंपनियों और व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू करे, जिसके तहत खाने के तेल के डिब्बों और पैकेटों पर "पुराना वजन", "नया वजन" और "प्रति किलो या प्रति लीटर वास्तविक कीमत" स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य किया जाए। इससे ग्राहक आसानी से समझ सकेगा कि उत्पाद की मात्रा में कितना बदलाव हुआ है और वह वास्तविक रूप से कितनी कीमत चुका रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।

दर्शनकुमार नायक ने कहा कि गुजरात जैसे उत्पादन सम्पन्न राज्य में यदि आम जनता को महंगे दामों पर कम मात्रा में तेल खरीदना पड़ रहा है तो यह केवल बाजार की समस्या नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता भी है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहें और उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की भ्रामक व्यापारिक नीति न अपनाई जाए।

उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य संबंधी अपील को गंभीरता से लिया है और लोग सीमित तेल उपयोग की दिशा में जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कंपनियों को अतिरिक्त मुनाफा कमाने के रूप में नहीं मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी केवल अपील करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि बाजार व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।

खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों और घटती पैकेजिंग का मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनता जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े उत्पादों में इस प्रकार के बदलाव का सीधा असर मध्यमवर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा गुजरात की राजनीति और बाजार व्यवस्था दोनों में चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।

माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने साबरमती रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

साबरमती स्टेशन से ट्रेन द्वारा दिल्ली के लिए किया प्रस्थान

आज दिनांक 13.05.2026 को गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने पुनर्विकसित किए जा रहे साबरमती रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान माननीय राज्यपाल ने साबरमती स्टेशन पर प्रदर्शित लघु मॉडल एवं स्टेशन पुनर्विकास योजना का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने माननीय राज्यपाल को साबरमती रेलवे स्टेशन तथा NHSRCL (बुलेट ट्रेन) स्टेशन परियोजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज पहली बार उन्हें साबरमती रेलवे स्टेशन देखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश एवं श्री अन्नु त्यागी द्वारा स्टेशन परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसे देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित एवं प्रसन्न हैं।

माननीय राज्यपाल ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया बुलेट ट्रेन अभियान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और विशेष रूप से गुजरात में इसका कार्य अत्यंत प्रभावशाली ढंग से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से देश के विभिन्न भागों के लिए संचालित हो रही ट्रेनों के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किए बिना इतना भव्य एवं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना अपने आप में अद्वितीय है तथा संभवतः भारत में पहली बार इस प्रकार का स्टेशन विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत सरकार की कैबिनेट द्वारा आज ही धोलेरा से साबरमती तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन परियोजना को लगभग 20,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही अहमदाबाद एवं गांधीनगर क्षेत्र मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है, जिससे यात्रियों को देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए उत्कृष्ट एवं निर्बाध कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

माननीय राज्यपाल ने कहा कि साबरमती स्टेशन को अत्यंत व्यवस्थित एवं आधुनिक रूप से विकसित किया जा रहा है, जहां आने वाली एवं जाने वाली ट्रेनों के लिए पृथक व्यवस्था होगी। बुलेट ट्रेन, मेट्रो तथा देश के विभिन्न भागों से आने वाली ट्रेनों का यह संगम भविष्य में एक दर्शनीय केंद्र बनेगा, जिस पर देशवासियों को गर्व एवं स्वाभिमान का अनुभव होगा। उन्होंने इस आधुनिक विकास कार्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा रेलवे प्रशासन एवं समस्त रेल अधिकारियों को श्रेय दिया।

माननीय राज्यपाल ने कहा कि वे आज रेलमार्ग से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तथा प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों से की गई अपील के अनुरूप उन्होंने संकल्प लिया है कि उनकी अधिकांश आगामी यात्राएं रेल एवं एसटी बसों के माध्यम से होंगी। उन्होंने बताया कि वे प्रत्येक सप्ताह गुजरात के विभिन्न तालुकाओं में किसानों के बीच जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तथा अनुसूचित जाति परिवारों के बीच समय बिताते हैं। अब वे इन यात्राओं को हवाई मार्ग के बजाय रेलवे एवं एसटी बसों के माध्यम से करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने काफिले को भी सीमित करते हुए केवल तीन वाहनों तक रखा है, ताकि देश के विकास एवं ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकें।

ग्रामीण विकास से महिला सशक्तिकरण तक: वडोदरा में ममता हिरपरा के कार्यकाल ने छोड़ी मजबूत प्रशासनिक छाप

वडोदरा। प्रशासनिक दक्षता, जमीनी विकास और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशील कार्यशैली के लिए पहचान बनाने वाली वडोदरा जिले की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर (DDO) श्रीमती ममता हिरपरा का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर तबादला कर दिया गया है। उनके स्थानांतरण की खबर सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिले के विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला एवं बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को गति मिली, जिसका प्रभाव अब गांवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।

साल 2023 में वडोदरा जिले में DDO के रूप में नियुक्त हुईं श्रीमती ममता हिरपरा ने तीन वर्षों से अधिक समय तक जिले में अपनी सेवाएं दीं। इस दौरान उन्होंने केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन ही नहीं किया, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वे कार्यालय तक सीमित रहने के बजाय लगातार गांवों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायतों का दौरा करती रहीं। इससे योजनाओं की निगरानी बेहतर हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रति भरोसा भी मजबूत हुआ।

महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उनके कार्यों को विशेष रूप से सराहा गया। वडोदरा जिले में कुपोषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने "कृष से कृष्ण तक" नामक विशेष परियोजना की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के तहत ढाई हजार से अधिक बच्चों को सुपोषित करने में सफलता मिली। कुपोषित

बच्चों को चिन्हित कर उन्हें संजीवनी केंद्रों में भर्ती कराने, स्वास्थ्य परीक्षण कराने और नियमित पोषण निगरानी सुनिश्चित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और कई परिवारों को इसका सीधा लाभ मिला।

श्रीमती हिरपरा ने आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य किया। उनके कार्यकाल में जिले में लगभग 250 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का लक्ष्य तय किया गया। कई केंद्रों में बच्चों के लिए बेहतर बैठने की व्यवस्था, पोषण सामग्री वितरण और साफ-सफाई की सुविधाओं को मजबूत किया गया। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों को नए स्टील के बर्तन उपलब्ध कराए गए, जिससे बच्चों को स्वच्छ वातावरण में भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में सुधार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी सक्रियता लगातार दिखाई देती रही।

शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे। प्राथमिक स्कूलों में नए क्लासरूम निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला पंचायत में पहली बार मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने की पहल की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करना था। प्रशासनिक स्तर पर इसे शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक संदेश देने वाला कदम माना गया।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लेबर बेड की खरीद सुनिश्चित की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली। स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि गांवों तक बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं प्रभावी रूप से पहुंचें। उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य और पोषण को लेकर विशेष अभियान भी चलाए गए, जिनमें महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनके नेतृत्व में कई आधारभूत परियोजनाएं आगे बढ़ीं। लगभग 200 ग्राम पंचायतों के लिए नए पंचायत भवनों का निर्माण, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर आवास और वडोदरा तालुका पंचायत के नए कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति मिली। इनमें से कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ अंतिम चरण में हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण प्रशासन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और पंचायत स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ाना था।

वित्तीय प्रबंधन और स्थानीय प्रशासनिक आय बढ़ाने में भी उनके कार्यकाल को सफल माना जा रहा है। फाइनेंस कमीशन के लगभग 80 प्रतिशत कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के टैक्स संग्रह में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। प्रशासन को ग्राम पंचायतों के माध्यम से लगभग 45 करोड़ रुपये की आय अर्जित करने में सफलता मिली। यह उपलब्धि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

श्रीमती ममता हिरपरा की प्रशासनिक शैली में अनुशासन और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन देखने को मिला। वे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करती थीं और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर देती थीं। कई ग्राम पंचायतों में उन्होंने स्वयं पहुंचकर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इससे स्थानीय प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही बढ़ी और विकास योजनाओं की गति तेज हुई।

उनके कार्यकाल की एक विशेष बात यह भी रही कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण और बाल सुरक्षा को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक जागरूकता से जोड़ने का प्रयास किया। कई अभियानों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। स्वयं सहायता समूहों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर उन्होंने ग्रामीण भागीदारी को बढ़ावा दिया।

स्थानांतरण के बाद एक बातचीत में श्रीमती ममता हिरपरा ने वडोदरा जिले के प्रति अपने विशेष लगाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वडोदरा में कार्य करते हुए उन्हें प्रशासनिक अनुभव के साथ लोगों से जुड़ने और ग्रामीण जीवन को करीब से समझने का अवसर मिला। उन्होंने इसे अपने जीवन की अमूल्य स्मृतियों का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि वडोदरा में बिताया गया समय उनके लिए केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सीखने और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने का महत्वपूर्ण अनुभव रहा।

उनके तबादले के बाद प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई पंचायत प्रतिनिधियों, महिला समूहों और स्थानीय लोगों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने ग्रामीण विकास को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन पर उतारने का प्रयास किया।

सोना वायदा में 9228 रुपये और चांदी वायदा में 18897 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा में 33 रुपये का सुधार

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 413077.96 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 63275.91 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 349802.05 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4881.23 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 51316.24 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 154851 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 164497 रुपये और नीचे में 154851 रुपये पर पहुंचकर, 153442 रुपये के पिछले बंद के सामने 9228 रुपये या 6.01 फीसदी की तेजी के संग 162670 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी मई वायदा 7072 रुपये या 5.74 फीसदी की तेजी के संग 130209 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मई वायदा 861 रुपये या 5.58 फीसदी की तेजी के संग 16292 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 153575 रुपये के भाव पर खूलकर, 163576 रुपये के दिन के उच्च और 153230 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 8739 रुपये या 5.71 फीसदी की तेजी के संग 161885 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 154083 रुपये के भाव पर खूलकर, 163475 रुपये के दिन के उच्च और 154083 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153442 रुपये के पिछले बंद के सामने 8615 रुपये या 5.61 फीसदी की तेजी के संग 162057 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सत्र के आरंभ में 290224 रुपये के भाव पर खूलकर, 301429 रुपये के दिन के उच्च और 290224 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 279062 रुपये के पिछले बंद के सामने 18897 रुपये या 6.77 फीसदी की तेजी के संग 297959 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 19051 रुपये या 6.79 फीसदी की तेजी के संग 299609 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 19040 रुपये या 6.79 फीसदी

कमोडिटी वायदाओं में 63275.91 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 349802.05 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 51316.24 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

की तेजी के संग 299600 रुपये प्रति किलो हुआ।

मेटल वर्ग में 7268.83 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 16.05 रुपये या 1.15 फीसदी बढ़कर 1406.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 1.65 रुपये या 0.46 फीसदी की तेजी के संग 364 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 8.3 रुपये या 2.2 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 386.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 1.25 रुपये या 0.61 फीसदी की तेजी के संग 204.6 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4565.84 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 9673 रुपये के भाव पर खूलकर, 9807 रुपये के दिन के उच्च और 9614 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 33 रुपये या 0.34 फीसदी की बढ़त के साथ 9756 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 35 रुपये या 0.36 फीसदी की मजबूती के साथ 9758 रुपये प्रति बैरल बोला गया।

इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा 270.6 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 274 रुपये और नीचे में 269.6 रुपये पर पहुंचकर, 270.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.3 रुपये या 0.48 फीसदी बढ़कर 272.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 1.4 रुपये या 0.52 फीसदी की तेजी के संग 272.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 1020 रुपये के भाव पर खूलकर, 2 रुपये या 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 995 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 32720.46 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 18595.78 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 5797.66 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 921.09 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 30.24 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 509.50 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 2824.78 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1720.54 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.10 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 11570 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 64503 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 21825 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 278269 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 43418 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8615 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22238 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 70136 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17861 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26923 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 9700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 30.8 रुपये की गिरावट के साथ 186 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 60 पैसे के सुधार के साथ 11.05 रुपये हुआ।

सोना मई 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 232 रुपये की बढ़त के साथ 310 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 350000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1011 रुपये की बढ़त के साथ 1764 रुपये हुआ। तांबा मई 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.91 रुपये की बढ़त के साथ 6.7 रुपये हुआ। जस्ता मई 410 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.54 रुपये की बढ़त के साथ 1.55 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 9700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 61.8 रुपये की गिरावट के साथ 133.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 70 पैसे की नरमी के साथ 9.1 रुपये हुआ। सोना मई 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 954.5 रुपये की गिरावट के साथ 461.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 825.5 रुपये की गिरावट के साथ 980 रुपये हुआ। तांबा मई 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7.42 रुपये की गिरावट के साथ 25.1 रुपये हुआ। जस्ता मई 357.5 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.78 रुपये की गिरावट के साथ 0.11 रुपये हुआ।